हिन्दी दैनिक
स्वाभिमान जागरण
RNI.No.- UPHIN/2021/84176
लखनऊ से प्रकाशित..
वर्ष : 04 अंक : 327 लखनऊ, शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026 पृष्ठ : 08 मूल्य : 1.00 रूपया

भारत-पोलैंड दोस्ती को नई उड़ान, पीएम मोदी बोले, एफटीए से खुलेंगे अवसर

एजेंसी
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने गुरुवार को नयी दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, तकनीक और आर्थिक सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से भारत–पोलैंड संबंधों के लिए नए अवसर खुलेंगे। मोदी ने कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और यूरोपीय बाजारों के साथ मजबूत होते संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को नई दिशा दे सकते हैं। वहीं, डोनाल्ड टस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र कहने पर गर्व जताया और कहा कि भारत तथा पोलैंड के हितों में कोई टकराव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में अपनी पोलैंड यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद पिछले दो वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए

गए हैं। मोदी के मुताबिक, भारत और पोलैंड के रिश्ते केवल कूटनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे साझा मानवीय मूल्यों और ऐतिहासिक संबंधों की भी अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के लोगों को भारत में मिले आश्रय का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जामनगर और कोल्हापुर के शाही परिवारों ने उस दौर में हजारों पोलिश बच्चों और परिवारों की मदद की थी। मोदी ने इस ऐतिहासिक प्रसंग को दोनों देशों के बीच लंबे समय से कायम मानवीय रिश्तों का प्रतीक बताया। भारत और पोलैंड के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। पोलैंड के पूर्व राजदूत एडम बुराकोव्स्की के अनुसार, दोनों देश सालाना द्विपक्षीय व्यापार को लगभग छह अरब डॉलर से बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। इसके लिए कारोबारी साझेदारी, निवेश और व्यापारिक मंचों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक भी सहयोग के संभावित प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत–ईयू मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक संबंधों को विस्तार देने में मददगार हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले डोनाल्ड टस्क ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी उनसे मुलाकात कर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। टस्क की भारत यात्रा 21 से 23 अक्टूबर तक निर्धारित है। नयी दिल्ली में भारत–पोलैंड बिजनेस फोरम में भाग लेने के बाद वह बेंगलुरु जाएंगे, जहां सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। डोनाल्ड टस्क की यह यात्रा 2010 के बाद किसी पोलिश प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों को उम्मीद है कि इस दौरे से रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और व्यापार, निवेश तथा तकनीकी सहयोग को नई गति मिलेगी।

अमित शाह का कांग्रेस–आप पर हमला, बोले, यमुना की सफाई के लिए 8,941 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू

एजेंसी
नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में यमुना नदी की सफाई और जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं के मौके पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड की 43 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर कुल 8,941 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है। इस दौरान शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में यमुना के पुनरुद्धार के लिए तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने विपक्ष पर विकास कार्यों के बजाय राजनीतिक बहाने बनाने का आरोप भी लगाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य पर काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। शाह के मुताबिक, इस बैठक में यमुना के पुनरुद्धार को लेकर दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय के सामने प्रधानमंत्री की योजना रखी गई थी। गृह मंत्री ने कहा कि कम समय में योजना के तहत 40 प्रतिशत से अधिक काम पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शुरू की गई परियोजनाओं में गंदे पानी के शोधन, सीवरेज व्यवस्था में सुधार और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने से जुड़े कार्य शामिल हैं। शाह ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य दिल्ली के हर घर तक सीवरेज कनेक्शन पहुंचाना और लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना है। उन्होंने यमुना की सफाई के लिए तीन साल की कार्ययोजना तैयार करने की भी बात कही। अमित शाह ने अपने भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाकर विपक्ष राजनीतिक बहाने बना रहा है। शाह ने दावा किया कि विपक्षी दल घुसपैठियों के वोट बचाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। गृह मंत्री ने ईवीएम और चुनावी

प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की चुनावी सफलता को इन आरोपों से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता विपक्ष की राजनीति को समझ चुकी है। शाह के ये बयान ऐसे समय आए हैं, जब मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप–प्रत्यारोप जारी हैं। हालांकि, वोट चोरी और घुसपैठियों के मतदान से जुड़े आरोपों पर शाह ने अपने भाषण में कोई विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अमित शाह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यमुना की सफाई को लेकर किए गए वादों के बहाने भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने यमुना में डुबकी लगाने का वादा किया था, लेकिन नदी की सफाई के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। शाह ने इस दौरान केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाने से जुड़ी घटना का भी जिक्र किया और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि यमुना के पुनरुद्धार के लिए वास्तविक और बड़े स्तर पर काम भाजपा सरकार ने शुरू किया है। ह मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता प्रदूषण कम करना, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करना और लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रस्तावित कार्ययोजना के जरिए यमुना की स्थिति में सुधार किया जा सकेगा। अपने संबोधन में शाह ने दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें इन समस्याओं के लिए संसाधनों की कमी का हवाला देती थीं, जबकि भाजपा सरकार ने कचरे के ढेर कम करने के लिए काम किया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दो वर्षों में कूड़े के पहाड़ों की जगह हरियाली और बगीचे दिखाई देंगे। शाह ने आम आदमी पार्टी पर आंदोलन के जरिए सत्ता हासिल करने के बाद भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया और पंजाब में उसकी सरकार को सत्ता से हटाने की बात कही।

संक्षिप्त खबरें

शिलांग में ईडी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला, दो दिन में सरकारी ठिकानों पर दूसरी वारदात

एजेंसी
शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग में वीरवार तड़के मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय वाले भवन पर पेट्रोल बम फेंके। दो दिनों में सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले की यह दूसरी घटना है। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सायम ने बताया कि लंगकिर्डिंग इलाके में स्थित भवन पर हमले से कोई संरचनात्मक नुकसान नहीं हुआ। अधिकारी ने कहा, भवन के अंदर तैनात सुरक्षाकर्मी को सुबह तक हमले की जानकारी नहीं थी। संदिग्धों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस संबंध में एक मामला दर्ज किया जा रहा है और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। बुधवार को सुबह लैतुमखरा इलाके में स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर भी इसी तरह के हमले की घटना हुई थी।

ई–मुद्रा मामले, सरकार ने जांच के दिए निर्देश

एजेंसी
मुंबई। डिजिटल सिग्नेचर और आम जनता तक पहुंच के लिए वेबसाइट्स को सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जारी करने वाली ई–मुद्रा को लेकर सरकार की ओर से सुरक्षा जांच के निर्देश के बाद, कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ई–मुद्रा के शेयर गुरुवार को दोपहर 2 बजे एनएसई पर 18.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 351.40 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। बीते तीन दिनों में शेयर 35 प्रतिशत तक गिर चुके हैं। सोमावर को शेयर 540.15 रुपए पर थे। इसके अलावा, बीते छह महीने में ई–मुद्रा के शेयर 30 प्रतिशत और बीते एक साल में 46 प्रतिशत से अधिक लुढ़क चुके हैं। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को बताया था कि उसने ई–मुद्रा में हुई एक सुरक्षा घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की है। ई–मुद्रा के डिजिटल सर्टिफिकेट ब्राउजर को यह पुष्टि करने में मदद करते हैं कि कोई वेबसाइट असली है या नहीं।

वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए फोर्स मोटर्स ने रोस्मर्टा के साथ साझेदारी की

एजेंसी
मुंबई। पुणे स्थित फोर्स मोटर्स ने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए रोस्मर्टा ऑटो रीसाइक्लिंग के साथ साझेदारी की है। बृहस्पतिवार को बयान में यह जानकारी दी गई। रोस्मर्टा ने कहा कि इस साझेदारी से फोर्स मोटर्स के ग्राहकों को उसकी सुविधा का लाभ मिलेगा और समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों को हटाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया उपलब्ध होगी। इस साझेदारी के तहत पात्र वाहनों के लिए जरूरी दस्तावेजी कार्रवाई और कबाड़ बनाने की प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। बयान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में संचालित अधिकृत पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधा (आरवीएसएफ) रोस्मर्टा प्रदूषण नियंत्रण, वाहन खोलने और सामग्री पुनः प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के जरिये समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों के पुनर्चक्रण के लिए पर्यावरण संबंधी मानकों के अनुरूप समाधान उपलब्ध कराती है।

जयशंकर की पीएम डोनाल्ड टस्क से मुलाकात

एजेंसी
नयी दिल्ली। भारत पहुंचे पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने गुरुवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग

बढ़ाने पर चर्चा हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात कर खुशी हुई। टस्क ने भारत और पोलैंड के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को अधिक मजबूत करने को लेकर अपने विचार साझा किए। गुरुवार को ही दिन में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड टस्क के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इस बैठक में दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बात करेंगे। चर्चा का मुख्य फोकस रक्षा निर्माण, व्यापार, नई तकनीक, अंतरिक्ष अनुसंधान और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा। इसके अलावा रूस–यूक्रेन युद्ध, भारत–यूरोपीय संघ (ईयू) संबंध और क्षेत्रीय व वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विचार–विमर्श होगा। डोनाल्ड टस्क बुधवार शाम नयी दिल्ली पहुंचे। उनका यह तीन दिन का आधिकारिक भारत दौरा रक्षा, व्यापार और रणनीतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से हो रहा है। हवाई अड्डे पर उनके आगमन पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने श्एक्ससश पर एक पोस्ट में कहा कि यह उच्च स्तरीय दौरा भारत–पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगा और दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को मजबूत बनाएगा। टस्क के साथ पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमान्स्की और एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। नयी दिल्ली में शीर्ष स्तर की बैठकों के अलावा पोलैंड का प्रतिनिधिमंडल नयी दिल्ली और बेंगलुरु में होने वाले व्यापारिक कार्यक्रमों में भी भाग लेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार, पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में यह टस्क की भारत की दूसरी यात्रा है। इससे पहले वह वर्ष 2010 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भारत आए थे। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात 2024 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने वारसॉ का ऐतिहासिक दौरा किया था। उसी दौरान भारत और पोलैंड के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। दिल्ली में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद टस्क बेंगलुरु जाएंगे। वहां वह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कारोबारी हितधारकों से मुलाकात करेंगे। भारत–पोलैंड बिजनेस फोरम का आयोजन 22 अक्टूबर को नयी दिल्ली और 23 अक्टूबर को बेंगलुरु में किया जाएगा।

सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत पर शायना एनसी का तंज, कहा, जमानत कोई जीत नहीं, कोर्ट की सख्त शर्त है

एजेंसी
मुंबई। शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को मिली जमानत

को जीत नहीं बल्कि कोर्ट की शर्त बताया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पहले आरएसएस की एबीसी जनाने की जरूरत है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को मिली जमानत पर शिवसेना की प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। कोर्ट ने एक साल तक शांति बनाए रखने को कहा है। यह दूसरी बार है जब इन्होंने बॉन्ड की शर्तों को तोड़ा है। ये लोग प्रदर्शनकारी नहीं हैं बल्कि आदतन कानून तोड़ने वाले हैं। यहां जमानत मिलना कोई जीत नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप 50,000 रुपए जमा करते हैं और शांति बनाए रखने का वादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि कोर्ट को भी लगा कि ये लोग अशांति फैला सकते हैं और यही सच है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शिवसेना की प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बारे में एबीसी भी नहीं जानते। आरएसएस की महिला शाखा, श्राष्ट्र सेविका समितिश की स्थापना 1936 में हुई और यह पिछले 87 सालों से काम करते चली आ रही है। आज 87 सालों में इससे 10 लाख महिलाएं जुड़ी हैं और 4,000 शाखाएं चल रही हैं, जो पार्टी खुद 130 सालों में महिला अध्यक्ष नहीं बना पाई। वो क्या बात कर रहे हैं? आरएसएस के बारे में क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आरएसएस से जुड़ी महिलाएं अपने देश के साथ हैं। आपके पार्टी की महिला आपके साथ हैं कि नहीं, ये तो नहीं पता है। आप पहले इस बारे में पता कीजिए। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड भागे और उसके बाद वायनाड छोड़कर रायबरेली भागे।

जंतर–मंतर प्रदर्शन केस में सीजेपी नेता सौरव–आशुतोष की मुश्किलें बरकरार

एजेंसी
नयी दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 13 अक्टूबर को जंतर–मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने पेश होने के लिए और समय मांगा है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अपराध शाखा ने इन दोनों नेताओं को पेश होने का निर्देश दिया था। उनके खिलाफ 13 अक्टूबर को जंतर–मंतर जाने के लिए एक निजी संपत्ति में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने और लोक सेवकों के काम में बाधा डालने के आरोप में दो अलग–अलग मामले दर्ज किए गए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि शांति भंग न करने का हलफनामा देने के बाद उन्हें बुधवार को रिहा कर दिया गया। हाल में दोनों मामले अपराध शाख को भेज दिए गए थे। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दास और रांका ने अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है तथा गुरुवार को उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस दोनों को नए सिरे से नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने का निर्देश दे सकती है।

एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

एजेंसी
अमरावती। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार परकला प्रभाकर 23 अक्टूबर को होने वाले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकर इस प्रदर्शन में कई प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों के साथ मंच साझा करेंगे। पीपल अगेंस्ट एसआईआर गठबंधन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी। प्रभाकर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और कामकाज की आलोचना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रदर्शन का समर्थन करते हुए लिखा, हर गली में जंतर–मंतर! शुक्रवार, 23 अक्टूबर, 2026। लोकतंत्र की बहाली के लिए जन मार्च। आइए, इस चुनौती का सामना करें। आयोजकों ने विपक्षी नेताओं को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है, हालांकि उनकी भागीदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा, अभिनेता प्रकाश राज और किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की बात कही गई है। आयोजकों ने हर हाथ में तिरंगा, हर गली में जंतर–मंतर का नारा देते हुए देशभर में विरोध दर्ज कराने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं

के नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा पैदा हो सकता है। उनका कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। हालांकि, चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण का उद्देश्य सूची को अद्यतन करना है। नाम हटाने और पात्र मतदाताओं के अधिकारों को लेकर उठाए जा रहे सवाल इस प्रक्रिया पर जारी विवाद का हिस्सा हैं। परकला प्रभाकर की राजनीतिक टिप्पणियों पर इसलिए भी ध्यान जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार में वित्त मंत्री हैं। इसके बावजूद प्रभाकर कई मौकों पर केंद्र सरकार की नीतियों और निर्णयों की आलोचना कर चुके हैं। वर्ष 2024 में उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे और इसे बड़े घोटालों में से एक बताया था। उन्होंने इस विवाद के राजनीतिक प्रभावों पर भी टिप्पणी की थी। अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं पर उनके विचार अक्सर सार्वजनिक बहस का विषय बनते रहे हैं। परकला प्रभाकर एक भारतीय अर्थशास्त्री, लेखक और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। उनका जन्म 2 जनवरी 1959 को आंध्र प्रदेश के नरसापुरम में हुआ था। वह आंध्र प्रदेश की राजनीति से जुड़े परिवार से आते हैं। उनकी मां परकला कालिकम्बा विधायक रही थीं, जबकि उनके पिता परकला शेषावतारम भी लंबे समय तक विधायक रहे और राज्य सरकार में मंत्री के रूप में काम किया।

भारत और पोलैंड के बीच हितों का टकराव नहीं

एजेंसी
नयी दिल्ली। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने गुरुवार को कहा कि भारत और पोलैंड के बीच हितों का कोई टकराव नहीं है और दोनों देश भरोसे, साझा मूल्यों और विचारों के आधार पर अपनी दोस्ती को सुदृढ़ कर रहे हैं। नयी दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री टस्क ने पीएम मोदी के साथ अपनी बातचीत को ष्सार्थक और महत्वपूर्णष बताया। उन्होंने कहा कि पोलैंड, भारत की परंपरा और इतिहास से प्रेरित है। उन्होंने कहा, हमने अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा पूरी की है कि पोलैंड और भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी को कैसे विकसित और मजबूत कर सकते हैं। इस साझेदारी को स्थापित करने का निर्णय अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की वारसॉ यात्रा के दौरान लिया गया था। आज, हमने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर इसके शुरुआती नतीजों की समीक्षा की और आने वाले वर्षों में हमारे सहयोग की प्राथमिकताओं को तय करने पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, हमारी बातचीत बहुत सफल रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि पोलैंड और भारत में बहुत कुछ समान है, बल्कि इसलिए भी है कि हमारे बीच कोई भेद नहीं है – सिवाय भौगोलिक दूरी के। पोलैंड और भारत के बीच तालमेल बहुत स्वाभाविक है। हमारे हितों में कोई टकराव नहीं है। हमारे बीच कोई ऐसा ऐतिहासिक मुद्दा नहीं है जो हमें बांटता हो। हम अपनी दोस्ती को भरोसे, साझा मूल्यों और विचारों – जैसे कि अहिंसा के विचार – पर गढ़ रहे हैं। टस्क ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र कहने पर गर्व है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका की सराहना करते हुए इसे अस्थिरता, अनिश्चितता और राजनीतिक उथल–पुथल के दौर में उम्मीद की एक किरण बताया। उन्होंने कहा, पोलैंड की महान सॉलिडेरिटी क्रांति अहिंसा पर आधारित थी, और हम आपकी परंपरा और इतिहास से बहुत प्रेरित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, ष्हम वैश्विक स्तर पर आपकी भूमिका का सम्मान करते हैं और सराहना करते हैं।

सम्पादकीय

तेल के खेल में मोहरा बना भारत

वैश्विक राजनीति पर दबदबा उसी का होता है, जो अर्थव्यवस्था को अपनी मर्जी से नचाना जानता है। एक समय था जब ग्रेट ब्रिटेन अपनी औद्योगिक क्रांति के कारण एक के बाद एक देशों को अपना गुलाम बनाता गया और औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर खुद की शक्ति और संपत्ति में अकूत इजाफा किया। आज ऐसा ही खेल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं, फर्क यही है कि भारत को गुलाम बनाए बिना उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आए हुए हैं। बुधवार को रूबियो गुजरात के जामनगर पहुंचे, जहां मुकेश अंबानी का बनाया तेल शोधन संयंत्र है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी यह तेल रिफाइनरी रूस और वेनेजुएला समेत कई देशों से कच्चा तेल लेती है और उसे रिफाइन करके तैयार ईंधन वैश्विक बाजारों में भेजती है। पाठक जानते हैं कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का आधी रात में अपहरण कर अमेरिका ने उन्हें अपनी जेल में रखा है और वेनेजुएला में अपने समर्थन से अंतरिम सरकार बना दी है। यानी वेनेजुएला के तेल के खजाने पर अब अमेरिका का अधिकार है। इधर अमेरिका के ही छेड़े युद्ध के बाद ईरान ने जब होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग बंद कर दिया तो दुनिया भर में ईंधन की आपूर्ति पर इसका असर पड़ा और तेल की कीमतों में एकदम से तेजी आई। भारत में कितने दिनों तक लोग खाली सिलेंडरों के साथ सड़कों पर थे, यह तो कोई भूला नहीं है। इस त्योहारी मौसम में भी महंगाई बढ़ने का बड़ा कारण तेल की महंगाई है। अमेरिका में भी ऐसे ही महंगाई आई है, लेकिन अगले महीने वहां मध्यावधि चुनाव है। जिसमें ट्रंप तेल की महंगाई के कारण घिरे हुए हैं। ऐसे वक्त में रुबियो भारत आए और सीधे मुंबई पहुंच कर वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर को भी बुलवा लिया। विदेश मंत्रालय कोई सूचना देशवासियों को देता, इससे पहले ही अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस बारे में इत्तला दे दी थी कि जब रुबियो मुंबई में रहेंगे तो विदेश मंत्री जयशंकर वहीं उनसे मिलेंगे। अब यही चलन हो गया है कि हमारी सरकार क्या करेगी, यह अमेरिका पहले बता देता है। ऑपरेशन सिंदूर भी अचानक बंद कर दिया गया, यह बात पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बताई और उसके कई घंटों बाद नरेन्द्र मोदी ने। राहुल गांधी जब इसे अमेरिका के सामने सरेंडर बताते हैं तो यह महज तंज नहीं, मौजूदा दौर की कड़वी सच्चाई है। एक वक्त था जब भारत के लिए शान से कहा गया था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लेकिन अब उसी हस्ती को मोदी सत्ता के लालच में मिटाने पर तुले हैं और शान से बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से उनका कितना गहरा याराना है। हालांकि इसकी बहुत भारी कीमत देश की जनता चुका रही है। ट्रंप को व्यापारिक और राजनैतिक कोई भी असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल मोदी सरकार रख रही है। चुनाव से पहले अमेरिका को डीजल की भारी जरूरत है और जामनगर रिफाइनरी यह जरूरत पूरी कर सकती है। ध्यान रहे कि वेनेजुएला के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। लेकिन वेनेजुएला में जब अघोषित तौर पर अमेरिका की ही सरकार है, तो यह कहना ज्यादा सही होगा कि भारत ही वेनेजुएला का तेल खरीद रहा है, अमेरिका तो केवल ले रहा होगा। बहरहाल बीते महीनों में भारत ने वेनेजुएला से लगभग 2.90 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया, जिसमें से 90 प्रतिशत जामनगर रिफाइनरी में आया। यहीं से फिर संशोधित तेल वैश्विक बाजार में बेचा जाता है। रिलायंस की एक रिफाइनरी अब अमेरिका में भी खुलने जा रही है। श्अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंगश नाम से टेक्सास में बन रही इस रिफाइनरी में सारा काम रिलायंस की मदद से होगा और मार्च में इस पर करीब 300 अरब डॉलर का सौदा हो चुका है। अब अमेरिका चाहता है कि भारत वेनेजुएला से ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदे और उसे रिफाइन कर अमेरिका के सुपुर्द कर दे। हालांकि अपनी इस चाहत को कूटनीतिक शब्दों में पिरोकर भारतीयों को बताया जा रहा है। जैसे रुबियो ने मंगलवार को मुंबई में पत्रकारों से कहा कि भारत एक रिफाइनिंग सुपरपावर है और बाजार पर पड़ रहे दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। हमें रिफाइनिंग सुपरपावर बता कर अमेरिका अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। मोदी इस बात को अच्छे से समझते हैं, लेकिन अंबानी और ट्रंप से अपनी नजदीकियों को वे ज्यादा महत्व देते हैं। वैसे ट्रंप ने इस बीच एक समझौता रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी किया है, जिसके तहत रूसी डीजल को वैश्विक बाजार में उतारा जाएगा। अब तक तो भारत को रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ थोपने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन अब ट्रंप ने भी अपना फायदा देखते हुए बात पलट दी है। पिछले सप्ताह ही भारत को भी ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर सौ प्रतिशत टैरिफ लगाने वाली धमकी से मुक्त किया है। मोदी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता सकते हैं, लेकिन असल में ट्रंप बार–बार भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ट्रंप भारत की क्षमताओं का दोहन कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सत्ता में बने रहने का इंतजाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान से भी नजदीकियां बनाए हुए हैं। मुंबई में मार्को रूबियो ने अमेरिका के लिए पाकिस्तान की अहमियत बताई और देशभक्ति का ढोल पीटने वाले संघी और दक्षिणपंथी लोग इस पर एक शब्द नहीं कह रहे हैं। गौरतलब है कि 2025 में जब मार्को रूबियो केवल सीनेटर थे तो उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो वे पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सुरक्षा सहायता में कटौती के लिए एक बिल पेश करेंगे। इस बयान पर उनसे मुंबई में सवाल किया गया कि क्या अब आपका रुख बदला है? क्या इस नीति में कोई बदलाव हुआ है?श तो रुबियो ने कहा, शहम दुनिया में कहीं भी होने वाले आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन अब मैं सीनेटर नहीं, विदेश मंत्री हूं। मुझे अमेरिका की विदेश नीति का संचालन करना है। इसके लिए हमें अलग–अलग देशों के साथ संबंधा बनाए रखने होते हैं, जिनमें वे देश भी शामिल हैं, जिनके साथ हमारे कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जिसके साथ हमें संबंध बनाए रखने होंगे। उसके पास परमाणु हथियार हैं। भौगोलिक स्थिति के लिहाज से भी हमें उसके साथ बातचीत और संपर्क बनाए रखने की जरूरत है। ठीक उसी तरह, जैसे भारत को ईरान के साथ संबंध रखने पड़ते हैं और वहां के नेताओं से मुलाकातें भी होती हैं। इस बयान से मार्को रुबियो ने बता दिया कि असीम मुनीर और शाहबाज शरीफ ट्रंप को प्यारे हैं और उनके आगे वे मोदी को अहमियत नहीं देते हैं। रूबियो ने जिस तरह भारत–ईरान संबंधों की तुलना पाकिस्तान से अपने रिश्तों को बताने के लिए की, वह भी सरासर देश का अपमान है, क्योंकि ईरान से हमारे सदियों पुराने संबंध हैं। और वह कोई आतंक फैलाने वाला देश नहीं है, जिसके नापाक इरादों को भारत का समर्थन रहता है। अमेरिका ने तो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में मदद की, लेकिन भारत ने ईरान के साथ ऐसा नहीं किया। ईरान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश बताकर अमेरिका ने उस पर हमला बोला, व्यापक प्रतिबंध लगाए, लेकिन जिस पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छिपा रहा, वहां ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अमेरिका भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और इन सबसे बढ़कर हमारे सम्मान पर लगातार किसी न किसी तरह चोट पहुंचा रहा है और सरकार इस पर चुप लगाकर बैठी है। इसके प्रत्यक्ष नुकसान तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन दो–तीन लोगों के फायदे के लिए जो दीर्घकालिक नुकसान देश को मोदी सरकार करवा रही है, वो और घातक साबित होंगे।

इतिहास की पाठ्यपुस्तकें: ज्ञान का विस्तार या वैचारिक संकुचन

अरुण कुमार डनायक

इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का लेखा–जोखा नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टि विकसित करने का माध्यम भी है। समाज अपने अतीत को किस तरह देखता है, किन घटनाओं को महत्व देता है और उनकी व्याख्या किन आधारों पर करता है, इससे उसकी सामूहिक चेतना निर्मित होती है। इसलिए विद्यालयों में इतिहास पढ़ाने का प्रश्न केवल पाठ्यक्रम या परीक्षा तक सीमित नहीं है। इसका संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र चिंतन से भी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुरूप शिक्षा को अधिक उपयोगी और विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुकूल बनाना है। नए शोध को स्थान देना और पुरानी त्रुटियों को सुधारना आवश्यक है, लेकिन बदलावों का मूल्यांकन उनकी नवीनता या सरकार के समर्थन के आधार पर नहीं, बल्कि उनके शैक्षणिक औचित्य, प्रमाणों की विश्वसनीयता, प्रस्तुति की निष्पक्षता और विद्यार्थियों के ज्ञान–विवेक पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर होना चाहिए। भारतीय इतिहास–लेखन स्वयं विभिन्न दृष्टिकोणों और बहसों से विकसित हुआ है। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारतीय अतीत को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में बांटकर धर्म को इतिहास की व्याख्या का प्रमुख आधार बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित इतिहासकारों ने इस दृष्टिकोण का प्रतिवाद किया और भारतीय अतीत को व्यापक सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों में समझने का प्रयास किया। बाद के दौर में धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी दृष्टिकोणों से प्रेरित इतिहासकारों ने जाति, वर्ग, उत्पादन संबंधों, धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक आदान–प्रदान का अध्ययन करते हुए भारतीय इतिहास की सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का विश्लेषण किया। इतिहास की विश्वसनीयता उसके प्रमाणों और स्रोतों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य, यात्रियों के वृत्तांत, साहित्यिक रचनाएं और धार्मिक ग्रंथ अलग–अलग प्रकार की जानकारी देते हैं। इसलिए किसी पौराणिक या साहित्यिक प्रसंग को ऐतिहासिक तथ्य मानने से पहले उसके रचनाकाल और संदर्भ की जांच आवश्यक है। किसी राजा को देवी से तलवार मिलने की कथा को प्रमाण के बिना ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता। इसी तरह, पर्दा और घूंघट को केवल इस्लामी आक्रमणों का परिणाम मानना भी सरलीकरण होगाय इनके विकास को व्यापक सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों में समझना चाहिए। परंपरा का सम्मान करने और उसके दावों की प्रमाणों के आधार पर जांच करने में कोई विरोध नहीं है। यही प्रमाण–आधारित दृष्टिकोण मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू होना चाहिए। कक्षा नौ की नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में राजपूतों, अहोमों, मराठों, सिखों और जाटों सहित विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के प्रतिरोध को प्रमुखता देना उचित है, विशेषकर यदि पहले उन्हें पर्याप्त स्थान नहीं मिला। लेकिन इतिहास को केवल आक्रमणों और युद्धों तक सीमित करने के बजाय उनके राजनीतिक–आर्थिक कारणों, शासकों के उद्देश्यों तथा उस दौर के सहयोग और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को भी समझाना आवश्यक है। नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में भारतीय मध्यकालीन इतिहास को अधिक स्थान

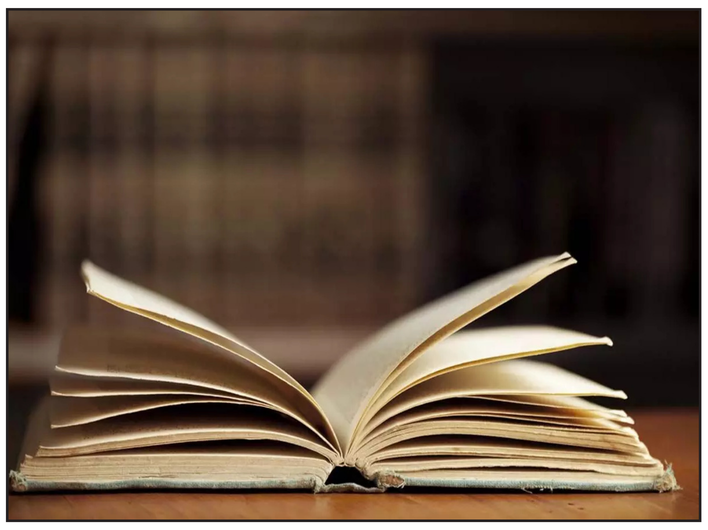

मिला है, जबकि फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियों, यूरोप में समाजवाद तथा नाजीवाद के उदय जैसे विषय पुरानी पुस्तक की तुलना में हट गए हैं। भारतीय इतिहास को अधिक स्थान देना अपने–आप में अनुचित नहीं, लेकिन विश्व इतिहास की इन महत्वपूर्ण घटनाओं को हटाने से विद्यार्थियों की ऐतिहासिक समझ कितनी व्यापक होगी, इस पर विचार आवश्यक है। मुगल शासकों और राजपूतों के संबंधों में संघर्ष और गठबंधन, दोनों देखने को मिलते हैं। अनेक राजपूत शासक मुगल प्रशासन और सेना में शामिल हुए, जबकि कुछ ने प्रतिरोध किया। विभिन्न मुस्लिम शासकों की नीतियां भी एक जैसी नहीं थीं और हिंदू शासकों के बीच भी सत्ता तथा संसाधनों के लिए संघर्ष होते थे। इसलिए किसी शासक के राजनीतिक निर्णयों को केवल उसकी धार्मिक पहचान से नहीं समझा जा सकता। धार्मिक स्थलों पर हमले, संरक्षण, जबरन धर्मांतरण और धार्मिक भेदभाव जैसी घटनाओं का उल्लेख प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। हिंसा को छिपाना और सहयोग व सहिष्णुता की उपेक्षा करना, दोनों अनुचित हैं। कुछ शासकों के कृत्यों के आधार पर पूरे समुदाय या सदियों के इतिहास को दोषी ठहराना उतना ही अवैज्ञानिक है, जितना असुविधाजनक तथ्यों को दबाना। स्वतंत्रता आंदोलन को भी व्यापक दृष्टि से समझना आवश्यक है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, भूमि–राजस्व व्यवस्था, उद्योगों पर प्रभाव, शिक्षा, प्रेस, सामाजिक सुधारों और किसान–मजदूर संघर्षों को समझे बिना इसकी कहानी अधूरी रहती है। गांधी, नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह और सरदार पटेल सहित विभिन्न नेताओं के योगदान के साथ उनके मतभेदों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन करोड़ों लोगों के संघर्ष और राजनीतिक चेतना का परिणाम था। विद्यार्थियों को केवल तारीखें याद कराने के बजाय घटनाओं के कारण, परिणाम और उनके ऐतिहासिक महत्व को समझने का अवसर मिलना चाहिए। प्राचीन भारत की गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, धातुकर्म, दर्शन और साहित्य संबंधी उपलब्धियों को पाठ्यक्रम में उचित स्थान मिलना चाहिए। उनका अध्ययन केवल गौरवगान तक सीमित न रहकर उस समय की बौद्धिक और सामाजिक परिस्थितियों, उनके व्यावहारिक उपयोग तथा ज्ञान के प्रसार को भी सामने लाए। वैदिक गणित की गणना–पद्धतियों का परिचय उपयोगी है, लेकिन उन्हें आधुनिक गणित का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। इसी संदर्भ में डार्विन के विकासवाद का प्रश्न महत्वपूर्ण है। कुछ कक्षाओं की पुस्तकों से इससे संबंधित सामग्री हटाए जाने पर वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने आपत्ति की थी। दशावतार और विकासवाद के बीच प्रतीकात्मक समानता देखी जा सकती है, लेकिन पौराणिक आख्यान वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रमाण नहीं हैं। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक अवधारणाओं का स्थान धार्मिक या वैचारिक मान्यताओं के बजाय उनके शैक्षणिक महत्व और वैज्ञानिक आधार से तय होना चाहिए। गणित और विज्ञान में संगणकीय चिंतन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए विषयों को स्थान देना उपयोगी है, बशर्ते इससे बुनियादी अवधारणाओं की समझ कमजोर न हो। इन बदलावों का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वे विद्यार्थियों को विषयों की गहरी समझ और स्वतंत्र तार्किक चिंतन के लिए कितना सक्षम बनाते हैं। इन बदलावों के संदर्भ में सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की जवाबदेही महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम संशोधनों के कारण और उनके आधार में प्रयुक्त शोध–सामग्री पारदर्शी होनी चाहिए तथा स्वतंत्र विशेषज्ञों की समीक्षा के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होना ही किसी बदलाव की शैक्षणिक उपयुक्तता का प्रमाण नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र और विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले नागरिक तैयार करना है। पाठ्यपुस्तकें ऐसी हों, जो विद्यार्थियों को अपनी परंपराओं से परिचित कराएं, अन्याय को न छिपाएं और न किसी समुदाय के प्रति अंधगौरव या घृणा पैदा करें, बल्कि प्रमाणों के आधार पर सोचने और प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करें। लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व इतिहास को अपनी उपलब्धियों के अनुकूल बनाना नहीं, बल्कि असुविधाजनक तथ्यों और आलोचनात्मक दृष्टिकोणों के लिए भी जगह सुनिश्चित करना है। इतिहास को बदलना समस्या नहीं हैय उसे सत्ता की वैचारिक जरूरतों के अनुरूप ढालना समस्या है।

(लेखक एवं समाजसेवी हैं)

रिजीम चेंज पर बवाल

रिजीम चेंज ये शब्द इस समय मोदी सरकार को बुरी तरह डरा रहा है। वैसे रिजीम चेंज कहें या सत्ता परिवर्तन या वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाएं, लोकतंत्र में ये जुमले गुनाह नहीं हैं, बल्कि उसकी बुनियादी शर्त हैं। जनता ही तय करती है, रिजीम यानी शासन करने का हक किसे दिया जाए और ठीक न लगने पर उसे कब उतारा जाए। इस परिवर्तन में जब तक कोई अनैतिक तरीके इस्तेमाल नहीं होते या गैरकानूनी काम और हिंसा नहीं होती, तब तक उसे गलत नहीं कहा जा सकता। मगर मोदी सरकार में जनता के विरोध को देशविरोध काम की तरह पेश किया जा रहा है। पहले राजनाथ सिंह ने रिजीम चेंज पर विपक्ष को घेरा, उसके बाद मोहन भागवत ने भी अपने विजयादशमी के भाषण में यही डर दिखाया और आंदोलन को गलत बताने की कोशिश की। इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू भी बांग्लादेश और फ्रांस का नाम लेकर भारत में उठे आंदोलन को गलत ठहरा सकते हैं। गौरतलब है कि आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और शिक्षा व्यवस्था की खामियां जैसे कई मुद्दों पर इस समय यूरोप के कुछ देशों में हिंसक आंदोलन खड़े हो चुके हैं। फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, अल्बानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ग्रीस में अलग–अलग आंदोलन चल रहे हैं। उसमें भी फ्रांस, इटली और अल्बानिया में स्थिति सबसे अधिक विस्फोटक हो चुकी है। अल्बानिया में तो सरकार पर कोई एक्शन न लेने के कारण सुप्रीम कोर्ट में ही आग लगा दी गई। वहीं फ्रांस में स्कूलों की बदहाली, योग्य शिक्षकों की भारी कमी और सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र के बजट में की गई भारी–भरकम कटौती के खिलाफ छात्र और शिक्षक पहले सड़कों पर उतरे फिर एक बड़ा जनआंदोलन खड़ा हो गया। जर्मनी में युवा वर्ग अनिवार्य सैन्य–सेवा योजनाओं और नीतियों का खुलकर विरोध कर रहा है। उधर इटली के मिलान सहित कई प्रमुख शहरों में भी प्रदर्शनकारियों ने भारी उत्पात मचाया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सार्वजनिक रूप से इन हिंसक हरकतों को कोरा अराजनीतिक उपद्रव और अराजकता करार दिया है। जिन देशों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ लोग हिंसा कर रहे हैं, वहां की सरकारें अगर इसे उपद्रव कहें तो समझ आता है। लेकिन भारत में तो हालात इसके उलट हैं। जुलाई में जंतर–मंतर की हिंसा की बात न भी करें, तो अभी अक्टूबर में हुए विरोधा प्रदर्शनों में भी दिल्ली पुलिस ने न केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर शक्ति का इस्तेमाल किया, बल्कि गैरकानूनी तरीके से उन्हें प्रताड़ित भी किया। इसके बाद भी भारतीय जनता जिस हिम्मत, धैर्य और सहनशक्ति के साथ शांति और अहिंसा को अपने प्रदर्शनों का हिस्सा बनाए हुए है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सरकार जनता के इस अद्भुत विवेक का लगातार अपमान कर रही है। अच्छी बात यह है कि जनता बार–बार यह साबित कर रही है कि हम गांधी का देश यूं ही नहीं हैं। आज की तारीख में गांधी भी अगर वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाते तो उन्हें ऐसे ही सलाखों के पीछे डाला जाता या उन पर भी लाठियां बरसतीं। यह सही है कि विपक्ष सड़कों पर उतरा और विपक्ष के आह्वान पर जनता भी सड़क पर उतर आई। इस वक्त सबकी यही मांग है कि जिन लोगों ने वोटों की चोरी की है, धांधली करके चुनाव जीता है, उन्हें सत्ता में बैठने का कोई हक नहीं है। अगर सरकार को इस मांग से ऐतराज है तो वह साबित करे कि उसने चुनावी धांधली नहीं की। इसके लिए सबसे पहले तो ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाया जाए, फिर एसआईआर में उठे सवालों का जवाब दिया जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए जो पहले व्यवस्था थी, यानी प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा देश के मुख्य न्यायाधीश की चयन समिति बनाई जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त को आजीवन कानूनी संरक्षण का प्रावधान भी खत्म किया जाए। यह सब मोदी सरकार कर ले तो फिर विपक्ष को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एसआईआर की जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने की जगह विपक्ष को अलोकतांत्रिक कहकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पिछली जुलाई में जंतर–मंतर पर हुई हिंसा पर विपक्ष ने लोकतांत्रिक तरीके से ही सदन में गृहमंत्री को जवाब देने कहा था, लेकिन पूरे मानसून सत्र में केवल आखिरी दिन अमित शाह लोकसभा में आए और वंदेमातरम् सुनकर चले गए। जुलाई से अब अक्टूबर आ गया, लेकिन इस सवाल का जवाब अमित शाह ने नहीं दिया कि पैलेट गन और एके 47 किसके आदेश पर चली। बल्कि अब नए सवाल भी जुड़ गए हैं कि प्रदर्शन के लोकतांत्रिक हक को मोदी सरकार क्यों कुचल रही है। क्यों पुलिस निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसा रही है। अमित शाह और नरेन्द्र मोदी अगर संसद में आकर इसका जवाब दे दें तो फिर विपक्ष और सामाजिक संगठनों को सड़क पर उतरना ही नहीं पड़ेगा। जनता तो दरअसल वही कर रही है जो गांधीजी ने रास्ता दिखाया था। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए बनी हंटर कमेटी के सामने सुनवाई के

राशिफल

मेष :– काफी दिनों से अवरोधित कोई हल होने के आसार बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में किया गया प्रयत्न सार्थक होगा। रोजगार में लाभकारी अवसर मिलेंगे।

बृषभ :– भावुकता व्यावहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी। अतः व्यवहार कुशल बने। भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं मन पर प्रभावी होंगी। विद्यार्थी शिक्षा में लापरवाही न बरतें। घर में खुशहाल वातावरण रहेगा।

मिथुन :– मूल्यवान समय को व्यर्थ के कायरें में जाया न करें। नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। सकारात्मक सोच को अपनाते हुए जीवन को सही दिशा की ओर केंद्रित करें और परिवार के अनुकूल चलें।

कर्क :– नये व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। संवेदनशील शरीर ग्रहां की प्रतिकूलता से बीमार पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन को निराश करेगी। पुरानी घटनाओं से मन को कष्ट संभव।

सिंह :– नयी घरेलू जिम्मेदारियों के पैदा होने से व्यय संभव। अच्छे कायरें से परिजनों के दिल में जगह बनायें। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। महत्वपूर्ण कायरें में लापरवाही कतई न करें।

कन्या :– जीवनसाथी के स्वास्य के प्रति सचेत रहें। नये कायरें के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा। नये क्षेत्रों में प्रयास से लाभ संभव। व्यावसायिक यात्रा द्वारा लाभ होगा। संबंधियों के सहयोग से कठिनाइयां दूर होंगी।

तुला :– भविष्य को लेकर मन नकारात्मक आशंकाओं से प्रभावी रहेगा। प्रतिभाओं के बावजूद भी हीन भाव प्रतिभाओं के लाभ से वंचित करेगा। सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। रोजगार में व्यस्तता रहेगी।

वृश्चिक :– रोजगार संबंधी कुछ नयी योजनाओं पर मन केंद्रित होगा। किसी कार्य में सफलता से उत्साह में वृद्धि होगी। कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुकूल चलने का प्रयत्न करें। भौतिक सुख में वृद्धि होगी।

धनु :– अपनी बातूनी कला का लाभ उठाएंगे। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन को निराश करेगी। परिश्रम से आर्थिक लाभ का योग है। समस्याओं के समाधान से उत्साह में वृद्धि होगी।

मकर :– बीती बातों को सोचने के बजाय वर्तमान में जीने की चेष्ठा करें। जरूरत से ज्यादा बोलना व्यक्तित्व पर कुप्रभावी होगा। अतरू इसे सुधारें। नीरस स्वभाववश रचनात्मक योजनाओं को सार्थक करने में असमर्थ होंगे।

कुंभ :– सब कुछ सामान्य होते हुए भी मन अरुचि का शिकार होगा। थोड़ा संयमी व धैर्यवान बने। भाग्य से प्राप्त सभी स्थितियों के मध्य समझौतावादी रवैया अपनायें। कुछ नई व्यस्तताएं सामने आएंगी। आलस्य कतई न करें।

मीनः– कुछ व्यासायिक कारणों से घर से दूर रहना पड़ सकता है। परिजनों की सुख–सुविधा के प्रति मन चिंतित होगा। मस्त–मौला मन ब्यर्थ के कायरे में समय जाया कर महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाह के प्रति मन चिंतित होगा। मस्त–मौला मन ब्यर्थ के कायरे में समय जाया कर महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाह होगा।

राष्ट्रीय एकता के सूत्र

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थापना दिवस पर होने वाले बहुचर्चित दशहरा संबोधन में संघ प्रमुख ने कहा कि हम सुनिश्चित करें कि हमारी समस्याओं का समाधान विरोध–प्रदर्शनों के बजाय समाज के भीतर से निकले। साथ ही कहा कि भारत को तोड़ने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। यह अतार्किक है कि सत्ता बदलने से परिस्थितियां बदल जाएंगी। अतीत में भी ऐसा नहीं हुआ और भविष्य में भी न होगा। दरअसल, देश में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एसआईआर में कथित अपारदर्शिता को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों और बाद में 'रिजीम चेंज' के बयानों के आलोक में भागवत ने ये टिप्पणी की। साथ ही यह भी कहा कि हाल के वर्षों में देश ने तमाम विषम–परिस्थितियों के बावजूद जो आशातीत प्रगति की है,उसे बाधित न कर पाने वाली विदेशी ताकतें हमारी एकता को तोड़ने की कोशिशें कर रही हैं। उनका मानना था कि जब विरोध–प्रदर्शनों की तपिश पर राजनीतिक दल रोटियां सेंकने लगते हैं तो आंदोलन का प्रयोग अराजकता व सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने में होता है। देश को विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग से भटकाने वाली विदेशी ताकतों से नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। भागवत ने कहा कि पश्चिम से उठा एक तूफान– संस्कृति, व्यवस्था व सुरक्षा आदि को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस बाबत फ्रांस, बांग्लादेश और नेपाल आदि के उदाहरण देकर, इन देशों में हुए आंदोलनों के निहितार्थों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में भी कुछ लोग ऐसी ही ताकतों का समर्थन करते नजर आते हैं। जिसके मूल में सत्ता हासिल करने की लालसा भी है। भागवत ने परतंत्र भारत में 'वंदे मातरम' को बंगाल की एकता के पर्याय के रूप में दर्शाया। उन्होंने कहा कि जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया तो समाज ने इसका दृढ़ता से विरोध किया। मजबूरन ब्रिटिश सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। विडंबना यह रही कि देश की आजादी के समय ऐसा न हो सका क्योंकि लोग नफरत में उलझ गए और राष्ट्रीय एकता को भूल गए। अंग्रेजों ने लोगों में यह धारणा बैठा दी कि हम अलग दिखते हैं, अतरू हकीकत में भी अलग और एक–दूसरे से दूर होने चाहिए। दरअसल, सांप्रदायिक और चरमपंथी विचारधाराओं का प्रभाव लोगों पर पड़ा। राजनीतिक वर्चस्व की लालसा और कुछ लोगों की स्वार्थपूर्ति के चलते हमने राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों का त्याग कर दिया। तुष्टीकरण की सोच के चलते राष्ट्र का विभाजन हुआ। दरअसल, भागवत की टिप्पणी उन बयानों के जवाब में थी, जिसमें एसआईआर में अनियमितताओं के विरोध में उपजे आंदोलन को सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बताया जा रहा था। संघ प्रमुख ने विकास से उपजी चुनौतियों पर भी दृष्टिपात किया। उन्होंने कहा कि विकास मनुष्य के लिए प्रतिकूल परिणाम पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। उनका इशारा विकास और पर्यावरण असंतुलन के कारण नेपाल मेंआई भयावह जलप्रलय की ओर था। उन्होंने भारत, चीन व नेपाल में विस्तृत हिमालय पर अनियोजित व पर्यावरण विरोधी विकास के खतरों के प्रति चेताया। साथ ही कहा कि विकास की कीमत लोगों को जान देकर नहीं चुकानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान व तकनीक की प्रगति से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए लेकिन यह विकास पर्यावरण और नैतिकता की अनदेखी न करे। साथ ही उन्होंने भारत की धार्मिक, भाषायी और खानपान की विविधता को अक्षुण्ण रखने पर भी बल दिया। दूसरी ओर आम नागरिकों की चिंता के साथ ही भागवत भी विदेशी शक्तियों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित सोशल मीडिया के खतरों के प्रति सचेत दिखे। उन्होंने माना कि ये लोगों को विवेक से हटाकर उनकी सोच को दुष्प्रभावित कर रहा है।

ऑडिट में खुला सिंचाई विभाग महाघोटाला

344 कर्मचारियों को बिना नियुक्ति दिए करोड़ों रुपए

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में फर्जीवाड़े की जड़ें इतनी गहरी निकलीं कि बिना नियुक्ति 344 कथित कर्मचारियों के खातों में 16 करोड़ रुपये पहुंचा दिए गए। ट्रेजरी में फर्जी खाते खुलवाकर एरियर भुगतान का खेला कर डाला। इसका खुलासा महालेखाकार की ऑडिट टीम ने किया है। विभाग में खलबली मची तो एकाउंटेंट को निलंबित कर एफआईआर दर्ज कर दी। अभी एक डिविजन में मामला मिला है। अब सवाल है कि इतने बड़े घोटाले में मिलीभगत का दायरा कहां तक फैला है और दूसरे डिविजनों में भी सरकारी धन की ऐसी ही लूट तो नहीं हुई सिंचाई विभाग के मिर्जापुर कैनाल डिविजन के लघु डाल पम्प कैनाल खंड में वित्तीय वर्ष 2025–26 में एकाउंटेंट और उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 16 करोड़ रुपये के एरियर भुगतान का घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि लघु डाल पम्प कैनाल डिविजन के 344 कर्मचारियों के फर्जी खाते खुलवाकर एरियर का भुगतान कर दिया गया है।महालेखाकार प्रयागराज की दस सदस्यीय टीम के वर्तमान वित्तीय वर्ष के ऑडिट में घोटाले का खुलासा हुआ तो एसडीओ के अधिशासी अभियंता व अन्य अफसरों में हड़कंप मच गया। अधिशासी अभियंता ने आनन–फानन में 18 अक्टूबर को विभाग के एकाउंटेंट व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी। मिर्जापुर कैनाल डिविजन के अधिशासी अभियंता को अन्य दस खंडों के कर्मचारियों के एरियर का भुगतान के लिए डीडीओ पावर दिया गया है। इसी डिविजन के लिपिक और एकाउंटेंट कर्मचारियों को किए जाने वाले एरियर का बिल बनाकर अधिशासी अभियंता से हस्ताक्षर कराने के बाद ट्रेजरी को भुगतान के लिए भेज देते हैं। ट्रेजरी से कर्मचारियों के बैंक खातों में भुगतान कर दिया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एमसीडी के एकाउंटेंट जितेंद्र कुमार ने लघु डाल पम्प कैनाल के 344 फर्जी कर्मचारियों के ट्रेजरी में खाते खुलवाकर 16 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया।सबसे बड़ी बात तो यह कि इन कर्मचारियों की विभाग में नियुक्ति भी नहीं है। इस जानकारी लघु डाल पम्प कैनाल डिविजन के अधिशासी अभियंता को हुई तो उन्होंने आपत्ति जताई। एमसीडी के अधिशासी अभियंता ने एकाउंटेंट जितेंद्र कुमार के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद निलंबित कर दिया।मिर्जापुर कैनाल डिविजन से जुड़े एक खंड के कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 2024–25 के एरियर का भुगतान 2026 में करना था। आरोप है कि भुगतान में अनियमितता बरतते हुए फर्जी खाते खुलवाकर 344 लोगों को करीब 16 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। ऑडिट टीम की जांच में इसका खुलासा हुआ है।महालेखाकार प्रयागराज की ऑडिट टीम ने वर्तमान वित्तीय वर्ष का ऑडिट 14 अक्तूबर से शुरू किया। ऑडिट टीम ने 16 अक्तूबर को जांच के दौरान लगभग 16 करोड़ रुपये के फर्जी एरियर भुगतान का मामला पकड़ लिया। एमसीडी में हड़कंप मच गया। एमसीडी के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार ने 18 अक्तूबर को शहर कोतवाली में एकाउंटेंट जितेंद्र कुमार व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।लघु डाल पम्प कैनाल के फर्जी कर्मचारियों को लगभग 16 करोड़ रुपये का एरियर भुगतान किए जाने के मामले की लीपापोती में सिंचाई विभाग के अधिकारी जुट गए हैं। सूत्रों की मानें तो घोटाले को दबाने के लिए शासकीय मद में इससे अधिक धनराशि भी जमा करा दी गई, जिससे मामले को दबाया जा सके। ऑडिट टीम ने अपनी जांच में इस मामले को पकड़ लिया। सिंचाई विभाग के अन्य डिविजनों में भी इसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है लेकिन खुलासा तभी हो पाएगा, जब अन्य डिविजनों के एरियर एवं अन्य मदों में किए गए भुगतान का ऑडिट किया जाएगा। अधिशासी अभियंता एमसीडी प्रमोद कुमार के अनुसार मामले का ऑडिट कराया जा रहा है। ऑडिट में जो भी पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एकाउंटेंट व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। यदि अन्य कर्मचारी शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

30 को लखनऊ आयेंगे अमित शाह, कसेंगे चूलें

संगठनात्मक बैठक में देंगे फतह मिशन 2027 का मंत्र

संवाददाता

लखनऊ। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृहमंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को लखनऊ आ सकते हैं। उनका इस दफे का दौरा जरा अलग होगा। वे संघटनात्मक मीटिंग में 2027 में होने वाले असेंबली इलेक्शन में फतह का मंत्र सुझाएं टीम और बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे। भाजपा की 30 और 31 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदेश कार्यसमिति की संगठनात्मक बैठक होगी जिसमें गृहमंत्री अमित शाह प्रदेश के चुनावी टिप्स दे सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह यूपी के बारे में बखूबी वाकिफ हैं। पहले भी अहम भूमिका निभा चुके हैं और नतीजा भी बेहतर रहा है।माना जा रहा है कि वह नवंबर में सभी बूथ अध्यक्षों एवं शक्ति केंद्र संयोजकों के साथ संवाद कर 2017 के चुनावी माडल को फिर से जमीन पर उतारेंगे। कार्यसमिति की मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्र एवं राज्य सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक एवं संगठन के चेहरे शामिल होंगे। कार्यसमिति की बैठक विधान सभा चुनाव से चंद माह पहले है, जिसके विशेष चुनावी मायने होंगे। पिछली प्रदेश कार्यसमिति 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में की गई, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन–2027 की रूपरेखा तय की थी।

लेकिन अब चुनाव सामने है। पार्टी के सामने कई चिंताजनक तस्वीरें हैं प्रदेश से लेकर क्षेत्रीय एवं जिला इकाइयों तक के गठन में हुई देरी को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष नाराजगी जता चुके हैं। युवा एवं अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश, क्षेत्रीय एवं जिला टीमें नहीं बनाई जा सकीं।यूजीसी आरक्षण एवं जेनजी आक्रोश जैसे विषय पार्टी की धड़कन बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े एवं सह प्रभारियों के सामने कार्यकर्ता ज्यादातर विधायकों के प्रति नाराजगी जता चुके हैं। उनका आरोप है कि संगठन में मूल एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं पर कई नए एवं बाहरियों को तवज्जो दी गई है। रणनीतिकारों का मानना है कि 2017 में प्रदेश प्रभारी रहते हुए अमित शाह ने माइक्रोमैनेजमेंट के जरिए रिकार्ड जीत दिलाई, वैसी ही पटकथा इस बार दोहराने की जरूरत आ पड़ी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर

लापरवाह ठेकेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई, ओमास, एफडीआर, एटीआर एवं जियो टैगिंग से संबंधित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण के निर्देश

संवाददाता

लखनऊ। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क, सुगम आवागमन और मजबूत ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास को गति देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास सड़क अभिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शिव सहाय अवस्थी एवं उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी राम भरत तिवारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जनपदों की परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों पीआईयू के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज–3 एवं फेज–4 के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति, निर्माण गुणवत्ता, पारदर्शिता, भुगतान, अभिलेखों के अद्यतन, अभियंताओं एवं ठेकेदारों की जिम्मेदारी तथा कार्यों में लापरवाही से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं सुधार कार्यों में निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीण आबादी को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध हो और कृषि मंडियों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान बने।मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आदेशों का पालन कराया जा रहा है बैठक में ग्रामीण मार्गों की वीसी, सीसी, ओमास, एफडीआर, एटीआर एवं जियो टैगिंग से संबंधित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कार्यों में अनावश्यक विलंब करने अथवा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन न करने वाले ठेकेदारों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए जाएं। नोटिस के बाद सुधार नहीं होने पर नियमानुसार ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही अभियंताओं को भी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। बैठक में 16 मार्गों की वर्तमान स्थिति ओमास पर दर्ज करने तथा 23 मार्गों से संबंधित एटीआर अपलोड करने के प्रकरणों की समीक्षा की गई। 46 मार्गों से संबंधित मामले पीआईयू स्तर पर लंबित पाए गए। इन सभी प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित करते हुए तत्काल निस्तारित करने तथा की गई कार्रवाई से मुख्यालय को पत्र एवं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। जिन जनपदों में कार्यों की प्रगति एवं निष्पादन संतोषजनक पाया गया, वहां के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। वर्चुअल बैठक में शिव सहाय अवस्थी एवं उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी राम भरत तिवारी, वित्त एवं लेखाधिकारी बृजेश कुमार, मुख्य अभियंता मायाराम गुप्ता, सूचना अधिकारी रतन कुमार सिंह, आईटी कोर्डिनेटर मुर्तजा सहित लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के 75 जनपदों के अभियंता तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राम ने यादव को मारा, अली के पास है

यूपी एमएलसी चुनाव की वोटर लिस्ट कर रही हैरान, गड़बड़ी की हद पार

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए वोटिंग कल 23 अक्टूबर को होगी। इन सीटों में पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। वोटिंग से पहले 21 अक्टूबर को चुनाव प्रचार थम गया है। कल वोटिंग ,सुधार की गुंजाइश तो नजर आती नहीं। इलाहाबाद झांसी स्नातक एमएलसी सीट की वोटर लिस्ट में अजबगजब एंट्री दिखाई दी है, जिससे राजनीति का पारा हाई हो सकता है। इलाहाबाद झांसी स्नातक सीट की वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम राम ने यादव को मारा मिला है। यही नहीं, पिता का नाम मूर्खचंद यादव है, साथ ही फतेहपुर में मतदाता के नाम के कॉलम में अली के पास है नाम दर्ज है। 23 अक्टूबर को वोटिंग से पहले वोटर लिस्ट में निकली गड़बड़ी बड़े सवाल खड़े करती है।चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी एमएलसी चुनाव में 152 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को की जाएगी। इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 को खत्म हो रहा है।

इन चुनावों के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। प्रदेश में कुल 2697 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 14 लाख 81 हजार 310 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा 3 लाख 13 हजार 531 वोटर हैं। इसके बाद वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 2 लाख 88 हजार 622 और इलाहाबादझांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 2 लाख 64 हजार 233 वोटर हैं।यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव भाजपा और सपा के लिए नाक की लड़ाई है।इस चुनाव को असेंबली इलेक्शन का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। यही कारण है कि इन 11 सीटों के लिए योगी सरकार के एक दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंक रखी थी। भाजपा और सपा के 100 से ज्यादा सांसदों और विधायकों ने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर प्रचार किया और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हरसंभव जुगत की। दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। पिछली बार इन सीटों पर सपा की बढ़त थी।उसने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा के खाते में 5 सीटें गई थीं।इस बार भाजपा की कोशिश है कि वह डबल डिजिट को छुए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा था। उन्होंने गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, आगरा गाजियाबाद समेत कई जिलों में उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं कीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोई भी जनसभा नहीं की, लेकिन चुनाव की जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को दी थी, ताकि वे डोरटूडोर जाकर मतदाताओं से पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके।

अमित शाह के जन्मदिन पर सीएम योगी ने दी बधाई

संवाददाता

लखनऊ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में शाह को कुशल रणनीतिकार और संगठन शिल्पी बताया। योगी ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने, सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने और सशक्त एवं सुरक्षित भारत के निर्माण में अमित शाह का योगदान अतुलनीय है। मुख्यमंत्री ने प्रभु श्रीराम से अमित शाह के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की प्रार्थना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि शाह आगे भी देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में अमित शाह के राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनके योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में नई दिशा देने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुभकामना संदेशों में अमित शाह के प्रशासनिक अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कार्यों को प्रमुखता दी गई।

नशे में वाहन चलाने के दुष्परिणामों को लेकर जन जागरूकता अभियान आज

अभियान के तहत निकलेगी पदयात्रा, होंगे नुक्कड़ नाटक और जनसंवाद कार्यक्रम

संवाददाता

लखनऊ। नशे में वाहन चलाने के दुष्परिणामों और सड़क सुरक्षा को लेकर कल 23 अक्टूबर को शहर में जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। कंज्यूमर वॉयस तथा लखनऊ स्थित उपभोक्ता अधिकार संगठन कंज्यूमर गिल्ड, जननायक सुजीत पांडेय चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से एकदिवसीय जागरूकता अभियान के दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में पदयात्रा, जनसंवाद और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जायेगा। कंज्यूमर वॉयस के परियोजना सलाहकार हेमंत उपाध्याय के मुताबिक जनजागरूकता अभियान की शुरुआत सुबह 7:30 बजे से 10:00 बजे तक पदयात्रा के आयोजन से होगी। यह पदयात्रा पांडेय कॉम्प्लेक्स, मोहनलालगंज से प्रारंभ होगी, जहाँ से प्रतिभागी आसपास के क्षेत्र में लगभग एक किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के संदेश को जन–जन तक पहुँचाने के लिए मोहनलालगंज बाजार और बलरामपुर अस्पताल के मुख्य द्वार पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा। इन जन–जागरूकता प्रस्तुतियों के माध्यम से सड़क पर जिम्मेदार व्यवहार और सुरक्षित वाहन चालन के महत्व को रेखांकित किया जाएगा। अभियान का मुख्य कार्यक्रम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र में आयोजित हितधारक एवं जन–संवाद होगा। इस संवाद में शराब और या अन्य नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाने से जुड़े जोखिमों, सड़क सुरक्षा की चुनौतियों, यातायात एवं सड़क सुरक्षा संबंधी कानूनों के पालन की आवश्यकता और दुर्घटनाओं की रोकथाम के व्यावहारिक उपायों पर चर्चा की जाएगी। कंज्यूमर वॉयस के परियोजना सलाहकार हेमंत उपाध्याय ने कहा, "शराब अथवा अन्य नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाने से बचकर ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इससे न केवल वाहन चालक, बल्कि उसमें सवार यात्रियों, पैदल चलने वालों और सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। सुरक्षित वाहन चालन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर जन–जागरूकता, कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और सभी संबंधित पक्षों की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। इसमें विशेष रूप से युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस अभियान के माध्यम से हमारा प्रयास जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना और लापरवाही से वाहन चलाने के गंभीर परिणामों के प्रति लोगों की समझ विकसित करना है। यह अभियान उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों के गंभीर परिदृश्य के बीच आयोजित किया जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2022 में शराब औरध्या अन्य नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाने के कारण 9,143 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 3,674 लोगों की मृत्यु हुई और 8,421 लोग घायल हुए। ए प्रभावी एवं व्यावहारिक उपायों को प्रोत्साहित करना है।

मडल श्रद्धा दुबे को नागपुर से खींचते हुए हजरतगंज थाने लाई एसटीएफ

कस्टडी रिमांड लेकर जुटाए जाएंगे सबूत

संवाददाता

लखनऊ। कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को एसटीएफ गुरुवार सुबह नागपुर से गिरफ्तार कर लखनऊ ले आई। मीडिया के कैमरों और तीखे सवालों से बचाने के लिए पुलिस तीनों को गाड़ी से उतारते ही खींचते हुए हजरतगंज थाने के अंदर ले गई। आरोपियों के चेहरे पहले से ही नकाब और रुमाल से ढंके हुए थे। हजरतगंज थाने में शुरुआती पूछताछ के बाद अब पुलिस और एसटीएफ ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस सबसे पहले तीनों का झलकारी बाई अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराएगी। इसके बाद नागपुर कोर्ट से मिली 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की समयसीमा खत्म होने से पहले

इन्हें लखनऊ की अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में पेशी के बाद पुलिस आरोपियों की रिमांड की मांग करेगी। कस्टडी मिलने पर पुलिस हत्याकांड से जुड़े पुख्ता सबूत जुटाएगी और वारदात की हर एक कड़ी को आपस में जोड़ेगी, ताकि घटना की सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। रिमांड के दौरान पुलिस मुख्य आरोपी श्रद्धा से कई बेहद अहम और उलझे हुए सवालों के जवाब उगलवाएगी। इनमें शिवा शर्मा की मौत के वक्त केवल अंडरवियर में होना, उसके चेहरे पर लिपस्टिक के निशान मिलना और शरीर पर सिगरेट से दागने के गंभीर जख्मों का राज शामिल है। पुलिस ने उन लोगों की लिस्ट पर भी काम शुरू कर दिया है जिन्होंने नागपुर से फरारी के दौरान श्रद्धा और उसके साथियों की मदद की थी। श्रद्धा की तरफ से फरारी के दौरान जारी किए गए वीडियो में जिन–जिन लोगों के नाम सामने आए थे, अब उन पर भी जांच की गाज गिरने वाली है। बता दें कि 9 अक्टूबर को श्रद्धा दुबे के चौथी मंजिल स्थित फ्लैट से गिरकर शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। मृतक की मां की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही श्रद्धा फरार चल रही थी, जिस पर इनाम भी घोषित किया गया था और आखिरकार वारदात के 12वें दिन 20 अक्टूबर को वह नागपुर में एसटीएफ के हत्थे चढ़ गई।

दिवाली से पहले जोन-7 के तीन वार्डो को मिलेगी सीवर समस्या से राहत, 1,200 से अधिक घरों को होगा फायदा

संवाददाता

लखनऊ। दिवाली से पहले लखनऊ नगर निगम के जोन–7 के तीन वार्डों, लाल बहादुर शास्त्री प्रथम, इंदिरा नगर और मैथिलीशरण गुप्त के लोगों को सीवर संबंधी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। वन सिटी वन ऑपरेटर परियोजना के तहत सीवर नेटवर्क के संचालन एवं रखरखाव का कार्य कर रही संस्था सुएज की टीम ने साईं मंदिर के पास क्षतिग्रस्त 600 एमएम व्यास की सीवर पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन डालने का कार्य पूरा कर लिया है। करीब छह मीटर की गहराई में पाइपलाइन डालने का कार्य सुएज के इंजीनियरों की निगरानी में आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ किया गया। संबंधित क्षेत्र में लगभग 50 वर्ष पूर्व आवास विकास विभाग द्वारा सीवर लाइन बिछाई गई थी। समय के साथ पुरानी

पाइपलाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे क्षेत्र में सीवर संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि मौके पर नए मैनहोल का निर्माण जारी है। निर्माण कार्य जल्द पूरा किए जाने की योजना है। इसके बाद लाइन को चालू करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नई पाइपलाइन के चालू होने से क्षेत्र के 1,200 से अधिक घरों को सीवर संबंधी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। सुएज के ऑपरेशन मैनेजर सोनपाल शर्मा ने बताया, जोन–7 में पुरानी और क्षतिग्रस्त सीवर पाइपलाइन के कारण स्थानीय निवासियों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सुएज की टीम लगातार कार्य कर रही है। साईं मंदिर के पास लगभग छह मीटर की गहराई में 600 एमएम व्यास की नई पाइपलाइन डालने का कार्य आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पूरा कर लिया गया है। फिलहाल नए मैनहोल का निर्माण कराया जा रहा है। शेष कार्य पूरा कर पाइपलाइन को जल्द चालू करने का प्रयास है, जिससे क्षेत्र के 1,200 से अधिक घरों को राहत मिल सकेगी।

स्नातक चुनाव के लिए 33 पोलिंग पार्टियां रवाना

संवाददाता

उरई/जालौन। इलाहाबाद–झांसी खंड स्नातक निर्वाचन–2026 के मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुक्रवार, 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए गुरुवार दोपहर उरई स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय से 33 पोलिंग पार्टियों को आवश्यक निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराकर उनके निर्धारित मतदान स्थलों के लिए रवाना किया गया। जनपद में इस चुनाव के दौरान कुल 20,999 स्नातक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी समीर की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री वितरित की गई। इसके बाद सभी मतदान दलों को उनके निर्धारित मतदेय स्थलों के लिए रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, सभी पोलिंग पार्टियों की उपस्थिति शत–प्रतिशत रही। मतदान को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुक्रवार को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके लिए जिले में 24 मतदान केंद्रों के अंतर्गत 33 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखने के लिए जनपद में पांच जोनल मजिस्ट्रेट और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रत्येक मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी के साथ तीन मतदान अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सभी 33 मतदेय स्थलों पर स्वतंत्र माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है, ताकि निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप मतदान संपन्न कराया जा सके। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के

लिए जनपद के सभी 33 मतदेय स्थलों पर 470 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, जिससे मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जिला प्रशासन ने निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। प्रशासन का लक्ष्य इलाहाबाद–झांसी खंड स्नातक निर्वाचन–2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना है। गुरुवार को पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के साथ ही मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। अब शुक्रवार को जिले के 20,999 स्नातक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

महिला से 41 लाख की ठगी,पुरानी करेंसी के बदले का लालच देकर जाल में फंसाया

संवाददाता

नोएडा। फेसबुक पर पुरानी करेंसी के बदले ज्यादा रकम देने का विज्ञापन देखकर एक महिला साइबर ठगों के जाल में फंस गई। आरोपियों ने जीएसटी और अन्य शुल्क के नाम पर महिला से करीब 41.45 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। बाद में रकम लौटाने के बजाय उसे धमकाने लगे। पीड़िता की शिकायत पर मंगलवार को साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है। सेक्टर–26 निवासी अनुराधा छेत्री ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने फेसबुक पर पुरानी करेंसी के बदले बड़ी रकम देने का विज्ञापन देखा था। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें वाट्सऐप और फोन कॉल के जरिए संपर्क किया। आरोपियों ने पुरानी करेंसी के बदले ज्यादा रकम दिलाने का भरोसा दिया। पीड़िता के मुताबिक, कुछ आरोपियों ने खुद को जीएसटी अधिकारी बताया। उन्होंने रकम जारी कराने के नाम पर जीएसटी और दूसरे शुल्क जमा करने को कहा। अलग–अलग बहाने बनाकर आरोपियों ने 1 से 13 अक्टूबर 2026 के बीच

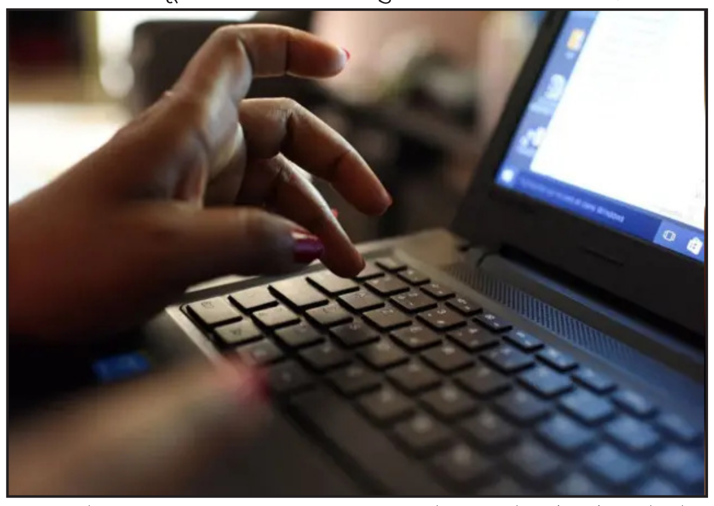

महिला से कुल 41 लाख 45 हजार 38 रुपये ट्रांसफर करा लिए। महिला ने बताया कि रकम वापस करने के बजाय आरोपियों ने कानूनी कार्रवाई की धमकी देना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें ठगी का पता चला और उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने पुलिस से संबंधित मोबाइल नंबरों, वाट्सऐप खातों और बैंक लेनदेन की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और ठगी की रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

80 गांवों की जमीन पर बसेगा नया शहर, 3 जगह लगेगे कैंप

संवाददाता

नोएडा। दादरी–नोएडा–गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (न्यू नोएडा) में दीपावली के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक 361 किसान आपसी सहमति से जमीन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। किसानों से दस्तावेज और सहमति पत्र लेने के लिए तीन जगह कैंप लगाए गए हैं। यहां पांच लेखपालों की टीम किसानों से संपर्क करेगी। प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण की समीक्षा कर अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुआवजे की दरें भी तय हो चुकी हैं। न्यू नोएडा में अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने के लिए तीन नए सर्किल–11, 12 और 14 बनाए गए हैं। सर्किल–11 की जिम्मेदारी जीएम एसपी सिंह को

दी गई है, जबकि सर्किल–12 और 14 का काम जीएम एके अरोड़ा संभालेंगे। जल्द ही इन सर्किलों में सीनियर मैनेजर और मैनेजर तैनात किए जाएंगे। पहले और दूसरे चरण में जमीन देने वाले किसानों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की व्यवस्था के अनुसार मुआवजा और 6 प्रतिशत आबादी भूखंड मिलेगा। तीसरे और चौथे चरण में जमीन देने वाले किसानों को यमुना प्राधिकरण की व्यवस्था के तहत मुआवजे के साथ 7 प्रतिशत आबादी भूखंड दिया जाएगा। न्यू नोएडा का मास्टर प्लान 20,911.29 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार किया गया है। इसमें 80 गांवों की जमीन शामिल होगी। शहर की अनुमानित आबादी करीब 6 लाख रखी गई है। इसे चार चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 2023 से 2027 तक 3,165 हेक्टेयर, दूसरे चरण में 2027 से 2032 तक 3,798 हेक्टेयर, तीसरे चरण में 2032 से 2037 तक 5,908 हेक्टेयर और चौथे चरण में 2037 से 2041 तक 8,230 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित करने की योजना है। पहले चरण की समयसीमा को देखते हुए प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने की तैयारी की है।

आरोपियों की गिरफ्तारी और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग

संवाददाता

बस्ती। अधिवक्ता अनिल चौधरी पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दोपहर 12.30 बजे संयुक्त बार के तत्वावधान में वरिष्ठ अधिवक्ताओं समेत सैकड़ों अधिवक्ताओं ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। अधिवक्ताओं ने कहा कि अनिल चौधरी पर हुए हमले के मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता

दिखाते हुए प्रशासन से प्रभावी कदम उठाने की मांग की। जनपद बार के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार पांडेय ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग उठाई थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए यह कानून लागू नहीं किया गया तो अधिवक्ता साथी विधानसभा का घेराव करेंगे। गौरतलब है कि अनिल चौधरी पर हमले के विरोध में सोमवार को भी अधिवक्ताओं ने न्याय मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया था। उस दौरान भी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग उठाई गई थी। गुरुवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं ने एक बार फिर अपनी मांगों पर कार्रवाई का दबाव बनाया। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदीप कुमार पांडेय, यंग बार के विनोद भट्ट, दुर्गेश श्रीवास्तव, सिविल बार के अजय सिंह, मारुति शुक्ल, रजनीश दुबे, राजेंद्र शुक्ल, अविनाश त्रिपाठी, रामकृपाल, अमर, शीतला शुक्ल, राधेश्याम यादव और अजीत पांडेय सिंह समेत सैकड़ों अधिवक्ता शामिल रहे।

केरल के नवजागरण पर सर सैयद अहमद खान के विचारों के प्रभाव पर व्याख्यान

संवाददाता

अलीगढ़। सर सैयद अहमद खान के प्रगतिशील विचारों और शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण ने केरल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण

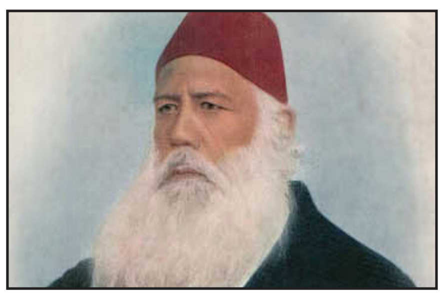

को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह बात प्रसिद्ध लेखक, विद्वान और विचारक डॉ. अजीज थरुवाना ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के मलयालम अनुभाग द्वारा सर सैयद दिवस समारोह के अंतर्गत आयोजित शैक्षणिक व्याख्यान में कही। उन्होंने "केरल नवजागरण और सर सैयद अहमद खान" विषय पर मुख्य व्याख्यान दिया। कोझिकोड स्थित फारूक कॉलेज के मलयालम विभागाध्यक्ष डॉ. थरुवाना ने समुदाय के सशक्तीकरण में आधुनिक शिक्षा और तार्किक चिंतन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शैक्षणिक सुधारों की सर सैयद की पैरवी का प्रभाव भाषाई और क्षेत्रीय सीमाओं से परे तक पहुंचा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के माध्यम से अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देने का सर सैयद का दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। डॉ. थरुवाना प्रतिष्ठित शिक्षाविद और लोक–साहित्य के विशेषज्ञ हैं। उनके शोधपरक ग्रंथ 'वायनाडन रामायणम' और वृत्तचित्रों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आधुनिक भारतीय भाषा विभाग की अध्यक्ष प्रो. ए. नुजुम ने अध्यक्षीय संबोधन दिया। मलयालम अनुभाग के प्रभारी रफसल बाबू सी. वी. ने स्वागत किया, जबकि तमिल अनुभाग के प्रभारी एवं सहायक प्रोफेसर डॉ. आर. तमिल सेल्वम ने अतिथियों का अभिनंदन किया। अरबी विभाग के शोधार्थी महबूब तालीपरंबा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

जेएन मेडिकल कालिज के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की चिकित्सका के पहले उपन्यास का विमोचन

संवाददाता

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. शहना अली के पहले उपन्यास 'द व्हाइट कोट्स वेट' का विमोचन एएमयू स्टाफ क्लब में आयोजित समारोह में किया गया। उपन्यास में चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों तथा सफेद कोट के पीछे छिपे मानवीय अनुभवों को प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए फारसी की प्रख्यात विद्वान प्रो. नाहिद अजरमी दुख्त सफवी ने उपन्यास की भावनात्मक प्रामाणिकता और साहित्यिक उत्कृष्टता की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह उपन्यास दूसरों का उपचार करने के लिए समर्पित लोगों की उन भावनात्मक कमजोरियों और आंतरिक अनुभवों को आवाज देता है, जिनके बारे में आमतौर पर बात नहीं की जाती। इसमें पेशेवर जीवन की वास्तविकताओं और गहरी मानवीय संवेदनाओं का सुंदर मेल है। मुख्य अतिथि प्रो. ए. आर. किदवई ने डॉ. अली की संवेदनशीलता और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि उपन्यास के विषय चिकित्सा जगत से आगे बढ़कर सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों से जुड़ते हैं। उन्होंने इसकी काव्यात्मक भाषा और मानवीय एवं पारिवारिक मूल्यों पर आधारित कथानक को भी सराहा। सर सैयद अकादमी के निदेशक और सम्मानित अतिथि प्रो. शाफे किदवई ने उपन्यास की साहित्यिक विशेषताओं तथा चिकित्सा पेशे की भावनात्मक वास्तविकताओं को रचनात्मक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करने के प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने शिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों की कलात्मक अभिव्यक्ति के महत्व पर भी प्रकाश डाला। चिकित्सा संकाय के अधिष्ठाता और अन्य सम्मानित अतिथि प्रो. मोहम्मद खालिद ने चिकित्सा पेशे से जुड़ी जिम्मेदारियों और भावनात्मक दबावों पर चर्चा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के जीवन में धैर्य, दृढ़ता और करुणा का विशेष महत्व है। उपन्यास की मुख्य पात्र डॉ. सना एक चिकित्सक है, जिसे गंभीर दीर्घकालिक बीमारी का पता चलता है। कहानी बीमारी को स्वीकार न करने की स्थिति से उसे स्वीकार करने तक के उसके सफर को दर्शाती है। इसमें चिकित्सकों के स्वयं मरीज बन जाने पर उनकी संवेदनशीलता, पेशेवर जीवन की चुनौतियों तथा पारिवारिक सहयोग और करुणा के महत्व को उजागर किया गया है। कार्यक्रम में लेखिका के पिता और प्रसिद्ध कथाकार प्रो. गजनफर अली, अंग्रेजी विभाग के प्रो. आसिम सिद्दीकी और प्रो. सामी रफीक, उर्दू कथाकार एवं आलोचक प्रो. तारिक छतारी, राजनीति विज्ञान विभाग के प्रो. मुहिबुल हक, चिकित्सा विभाग की डॉ. लुबना जफर और डॉ. अमीना ने भी विचार व्यक्त किए। लेखिका की बेटी इंशा ने उपन्यास लिखने में अपनी मां के समर्पण और मेहनत के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. शारिक अकील ने किया। धन्यवाद ज्ञापन में डॉ. शहना अली ने अपने परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने पुस्तक को पाठकों तक पहुंचाने के लिए नामक पब्लिकेशंस का भी धन्यवाद किया।

एएमयू की कुलपति ने शहजादा इदरीस बदरुद्दीन के निधन पर जताया शोक

संवाददाता

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु और एएमयू के पूर्व कुलाधिपति हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के छोटे भाई शहजादा इदरीस बदरुद्दीन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शहजादा इदरीस का 20 अक्टूबर को मुंबई में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्ष 1952 में दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु मरहूम हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के पांचवें पुत्र के रूप में जन्मे शहजादा इदरीस ने लगभग पांच दशक तक सामुदायिक सेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। शिक्षा उनके जीवन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल रही। उनके मार्गदर्शन में समुदाय के विद्यालयों के वैश्विक नेटवर्क का विस्तार हुआ और विभिन्न देशों में हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने शैक्षणिक मानकों को बेहतर बनाने, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को भी प्रोत्साहित किया। यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में हिज होलीनेस के विशेष प्रतिनिधि के रूप में तथा दुबई स्थित सुल्तान अल–बोहरा फाउंडेशन की परिषद

के सदस्य के तौर पर उन्होंने भारत से बाहर भी शांति, सद्भावना और सेवा का संदेश पहुंचाया। शोक व्यक्त करते हुए एएमयू की कुलपति प्रो. नइमा खातून ने कहा कि शहजादा इदरीस बदरुद्दीन के निधन से शिक्षा जगत ने एक ऐसे कर्मठ और समर्पित व्यक्तित्व को खो दिया है, जिन्होंने लगभग पांच दशक तक शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया। उन्होंने अनेक देशों में विद्यालयों के विकास, पाठ्यक्रमों को मजबूत बनाने और शिक्षकों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों से संवरने वाले अनगिनत युवाओं के जीवन में उनकी विरासत सदैव जीवित रहेगी। उन्होंने कहा कि एएमयू का हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ गहरा और स्थायी संबंध रहा है। कुलाधिपति के रूप में उनके दो कार्यकालों के दौरान विश्वविद्यालय को उनका स्नेह और उदार सहयोग प्राप्त हुआ। इस दुख की घड़ी में एएमयू का पूरा परिवार हिज होलीनेस और शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने प्रार्थना की कि परमात्मा इस अपूरणीय क्षति को सहन करने के लिए परिवार को धैर्य और शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को अपनी असीम कृपा से नवाजे। सहकुलपति प्रो. मोहम्मद मोहसिन खान ने कहा कि शिक्षा के प्रति शहजादा इदरीस का आजीवन समर्पण अनगिनत युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। कुलसचिव प्रो. आसिम जफर ने कहा कि उनका निधन केवल दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा और सेवा को महत्व देने वाले सभी लोगों के लिए गहरी क्षति है। दोनों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

5 नवंबर को 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ' अभियान के तहत मार्च निकालेगी भाजपा

संवाददाता

बस्ती। जिले में भाजपा 5 नवंबर को 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ' अभियान के तहत मार्च निकालेगी। पार्टी का जनजागरण अभियान 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगा। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित संगठनात्मक बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं से अभियान को प्रभावी बनाने का आह्वान किया। हरीश द्विवेदी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता से सीधा संवाद, पारदर्शिता और जनभागीदारी जरूरी है। कार्यकर्ता हर बूथ तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों, जनता की आवाज और जनकल्याण की राजनीति को प्राथमिकता देती है। बैठक में विपक्षी दलों पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में जनजागरण की रणनीति पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं से 5 नवंबर को प्रस्तावित मार्च को सफल बनाने और पार्टी की नीतियों, कार्यों तथा उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की गई। बैठक में संगठन को अधिक सक्रिय बनाने और अभियान के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने पर भी जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने की। जिला प्रभारी एवं क्षेत्रीय महामंत्री सत्येंद्र सिन्हा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

फायरिंग पीडित परिवार को धमकी,एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार

संवाददाता

बांदा। जनपद के बिसंडा थाना क्षेत्र के ओरन कस्बे में फायरिंग के मामले में पीडित ने गुरुवार दोपहर को 2 बजे पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर परिवार की सुरक्षा की मांग की है। आरोप है कि घटना के बाद से आरोपी पक्ष के तीन फरार लोगों और उनके परिजनों की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पीडिध्त ने लाइसेंसी असलहे लहराकर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। कुलदीप शिवहरे ने प्रार्थना पत्र में बताया कि 20 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे कुछ लोगों ने एकराय होकर उसे जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग की थी।वह बाल–बाल बच गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि मौके पर मौजूद ओरन चौकी के पुलिसकर्मियों के सामने भी उसे जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में बिसंडा पुलिस ने गोलू द्विवेदी पुत्र हरीनारायण द्विवेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि तीन अन्य आरोपी फरार हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घटना के बाद से आरोपी पक्ष के परिजन लाइसेंसी असलहे लहराकर उसके और परिवार के सदस्यों को धमका रहे हैं। इससे पूरा परिवार डरा हुआ है। उसने यह भी बताया कि 21 अक्टूबर को देवी विसर्जन के दौरान शाम करीब छह बजे आरोपियों ने अपने साथियों के साथ उसके चाचा और अन्य लोगों पर चौराहे पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। कुलदीप ने पुलिस अधीक्षक से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, आरोपी पक्ष के परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है।

स्वाभिमान जागरण
हिन्दी दैनिक
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एंव सम्पादक इम्तियाज़ अंसारी द्वारा सुपीरियर प्रिन्टर्स 245 माहम सिटी तिकोनिया पारा लखनऊ,(उ०प्र०)–11 से मुद्रित एवं मीडिया हाउस 20ए शिवाजीमार्ग हुसैनगंज लखनऊ उ0प्र0–01 से प्रकाशित।
संपादक
आलोक कुमार केसरवानी
प्रधान संपादक
इम्तियाज़ अंसारी
6392273876
Email-dainikswabhimanjagran.india@gmail.com
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं अस्थाई है
समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ मान्य होगा।